

परिपत्र

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व पात्रता सूची में अंकित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सम्बन्धित विभागीय जांच/अभियोजन की स्थिति ज्ञात की जाती है। किन्तु प्रायः यह देखा गया है कि सूची में एक ही नाम के एक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी होने के कारण विचारण सीमा में आने वाले वास्तविक व्यक्ति की रिपोर्टिंग नहीं की जाकर उसी समान नाम के अन्य व्यक्ति की विभागीय जांच/अभियोजन सम्बन्धित होने की रिपोर्टिंग कर दी जाती है। इस प्रकार की गई गलत रिपोर्टिंग के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचारण सीमा में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की सिफारिश हो जाती है। जब वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है तो नियुक्ति अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की त्रुटियों का निराकरण हेतु कार्मिक विभाग से यह परामर्श लिखा जाता है कि इस त्रुटि को सुधारने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंधान का पुनरावलोकन किया जावे अथवा नहीं ?

उक्त बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया तथा यह निर्णय लिया गया है कि जिस त्रुटि के कारण विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय तारतः प्रभावित नहीं होता है, उसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंधानों का पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक नहीं है। चूंकि इस प्रकार के मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का चयन कर लिया गया है किन्तु विभागीय जांच/अभियोजन के सम्बन्धित होने की गलत रिपोर्ट के आधार पर उसका चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की अनुसंधान कर दी गई है अतः ऐसे प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंधानों का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वास्तविक रूप में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/अभियोजन सम्बन्धित ही नहीं है और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पूर्व में की गई अनुसंधान तारतः यथावत रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है।

63/2001

अतः सभी नियुक्ति अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंधान का पुनरावलोकन करने का प्रस्ताव सहमति हेतु कार्यालय विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु सम्बन्धित व्यक्तियों का खन्ट लिफाफा बोलते हुए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुसंधान की प्रतियाँ निम्नी/प्रतियाँ/प्राप्त की जायेंगी।

*[Handwritten Signature]*  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को तृपना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- समस्त प्रमुखा शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित।
- 3- शासन सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।

*[Handwritten Signature]*  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

- 11- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
- 12- सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
- 13- परीक्षक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/कोटा।
- 14- परीक्षक, राजस्थान शिक्षण सेवा आयोग, जयपुर।
- 15- सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु 271 विभाग, कोटा।
- 16- सहित।
- 17- रक्षित पत्रावली।

*[Handwritten Signature]*  
शासन उप सचिव

63/2001